B-4

L-17

MIH

ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास

सरकारी प्रयास - 1757-1813 के मध्य :-

- प्रारम्भिक चरण में कम्पनी के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए विशेष रुचि नहीं ली गई इसका एक मुख्य कारण था शिक्षा में निवेश और व्यापार संतुलन के बीच कोई लाभदायक संबंध नहीं था।
- हालाँकि कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई- जैसे -1781 में कलकत्ता मदरसा, 1784 में एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल को विलियम जोंस के द्वारा स्थापित किया गया, 1791 में बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा तथा 1800 में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना वेलेजली द्वारा की गयी।
- इन संस्थाओं की स्थापना का संबंध भारत में शिक्षा का विकास नहीं था, बल्कि भारतीय परिस्थितियों और भारतीय भाषाओं को समझने के उद्देश्य से इन्हें स्थापित किया गया था जिससे भारत पर प्रभावी तरीके से शासन किया जा सके।
- भारत में शिक्षा एवं सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का एक आंशिक कारण ब्रिटेन एवं भारतीय प्रशासन पर प्राच्यवादियों का प्रभाव था।
- इनका दृष्टिकोण था कि भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का सम्मान करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform © KHAN SIR ©

नोट • प्राच्यवादी :-

• ब्रिटिश विचारकों प्रशासकों का एक समूह, इनमें प्रमुख थे - वारेन हेस्टिंग्स, थामस मुनरो, एलफिंस्टन, विलियम जोंस, प्रिंसेप, विल्सन इत्यादि।
• यदि भारत में आधुनिक परिवर्तन करना है तो धीरे-धीरे कदम उठाए जाए और भारतीय भाषाओं के माध्यम से आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास किया जाए।

• आंग्लवादी :- ब्रिटिश विद्वान प्रशासकों का समूह जो अंग्रेजी भाषा शिक्षा पद्धति और ब्रिटिश संस्कृत को श्रेष्ठ मानते है और भारतीय संस्कृत को निकृष्ट मानते है साथ ही भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन मे हस्तक्षेप का समर्थन करते है और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा पद्धति के विकास का भी समर्थन करते है इनमें प्रमुख थे - मैकाले, विलियम बेंटिंक और बड़ी संख्या मे ईसाई धर्म प्रचारक आदि।

उपनिवेश-बाद का दूसरा चरण एवं शिक्षा- 1813-1858 :-

• 1813 के अधिनियम में प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए एक लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया पहली बार भारत में कम्पनी एवं अंग्रेजों की सरकार ने नियमित रूप से शिक्षा के विकास के दायित्व को स्वीकार किया।
• इस राशी को किस प्रकार खर्च किया जाए इसको लेकर आंग्ल एवं प्राच्य समर्थकों के बीच विवाद हुआ।

KGS IAS

आंग्ल समर्थक अंग्रेजी भाषा में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति पर खर्च करना चाहते थे वहीं प्राच्य समर्थक भारतीय भाषाओं में भारतीय शिक्षा पद्धति तथा धीरे-धीरे यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान पर भी खर्च के पक्ष में थे।

- इस विवाद को आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहते हैं, विवाद के कारण 1823 ई. तक यह राशी भी खर्च नहीं की गई।
- 1823 में ही जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नामक एक संस्था बनाई गई।
- इसका उद्देश्य था शिक्षा नीति की दिशा को तय करना था यह भी आंग्ल प्राच्य विवादों मे फँसी रही।
- 1835 में मैकाले ने शिक्षा नीति पर एक परिपत्र तैयार किया जिसे बैंटिक ने अनुमति प्रदान की। इसके स्वरूप पर बल दिया गया कि शिक्षा की राशी को अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी और कुछ ही शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जाएगा तथा उनमें पढ़ने वाले भारतीयों का दायित्व होगा कि समाज के अन्य वर्गों को वे शिक्षित करे इसे 'अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत' भी कहते हैं। (Downward filtration theory)
- 1850 तक कई शहरों में सरकारी स्कूल खोले गए जैसे - दिल्ली, कलकत्ता, बाम्बे, मद्रास इत्यादि
- शिक्षा की विकास के दृष्टिकोण से 1854 के वुड्स डिस्पैच (मैग्नाकार्टा) का विशेष महत्व है जो कि भारत की भावी शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई।

मुख्य बिंदू

- भारत में उच्च शिक्षा का विकास अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक शिक्षा का विकास भारतीय भाषा में होगा।
- प्रत्येक प्रांतो में एक शिक्षा विभाग होगा।
- निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रावधान किए गए
- महिला शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के विकास का भी प्रावधान किया जाए।
- लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, बम्बे व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएंगे।
- अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को औपचारिक तौर पर छोड़ने की बात कही गई।

नोट -

- 1857 में तीनों शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए
- 1846-47, रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कालेज खोला गया।
  1858 में - मद्रास एवं पूना में भी इंजीनियरिंग कालेज खोला गया
  1835 में - कलकत्ता में मेडिकल कालेज खोला गया

द्वितीय चरण की आलोचना -

- 1813 में सरकार ने शिक्षा का दायित्व ग्रहण किया इसका मुख्य कारण भारत को आधुनिक बनाना

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

नहीं था बल्कि भारत में बाजार के विस्तार और प्रशासन मे सहयोग करने वाले तथा अंग्रेजी जानने वाले तथा कम पैसे पर काम करने वाले भारतीयों की आवश्यकता थी।
लेकिन इसी उद्देश्य से शिक्षा नीति में परिवर्तन किया।

भारत में शिक्षा के विकास को लेकर सरकार कितना गम्भीर थी इसे शिक्षा के लिए निर्धारित राशी (एक लाख रुपये) उस राशी को भी खर्च न कर पाना तथा अधोगामी निस्यदन नीति के सन्दर्भ में देख सकते हैं।

- कम्पनी की शिक्षा नीति में (अंग्रेजों की) तकनीकी शिक्षा, महिला शिक्षा एवं स्वदेशी भाषा मे शिक्षा तथा आम लोगों की शिक्षा की उपेक्षा की गई।
- शिक्षा व्यवस्था में शहरों का महत्व बढ़ा और (यह पैसे वालों के लिए ज्यादा सुलभ थी।

तृतीय चरण - 1858 - 1947 - वुडस डिस्पैच का विस्तार :

- वुडस डिस्पैच की प्रगति की समीक्षा के लिए तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास पर सुझाव देने के लिए 1882-83 में हंटर आयोग का गठन।
- कर्जन - 1899 - 1905 —

उच्च शिक्षा पर विचार विमर्श के लिए 1901 में शिमला मे सम्मेलन बुलाया गया 1902 में थामस रैले की अध्यक्षता मे एक आयोग बनाया गया और इस आयोग की अनुशंसा पर सन् 1904 में विश्वविद्यालय

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अधिनियम पारित किया गया। जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया गया।

- 1913 में निःशुल्क शिक्षा को लेकर एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया।
- 1917 में एक सैडलर आयोग बनाया गया। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण की आलोचना की।
- 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति की स्थापना की गई।
- 1937 में वर्धा शिक्षा योजना - जाकिर हुसैन समिति के द्वारा इसे तैयार किया गया।
- इस योजना में मातृभाषा में शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया।
- यह गाँधी जी के बेसिक शिक्षा पर आधारित था।
- 1944 - सार्जेन्ट योजना ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया था।
- 1948 में राधाकृष्ण आयोग की स्थापना और इनके द्वारा (यूजीसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR